

कश्मीर रियासत : नेहरू और पटेल की भूमिका

सारांश

भारत विभाजन एक ऐसा दंश है जो प्रत्येक देशवासी को आज भी चुभता है। सर्वधर्मभाव वाले इस लोकतंत्र में यह घटना एक ऐसा कृत्य है जिसने इससे प्रभावित होने वाले लोगों के विकास को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित किया, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव जम्मू-कश्मीर राज्य पर पड़ा जिसकी वर्तमान स्थिति यह सब कुछ साबित करने के लिए काफी है। जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियां इसको एक अलग ही दर्जा प्रदान करती हैं तथा इसके प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण ही इसको भारत में धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है।

जम्मू-कश्मीर की वर्तमान स्थिति के लिए देश विभाजन, भारतीय स्वतंत्रता के समय की राजनैतिक परिस्थितियां, नेहरू व पटेल की भूमिका को माना जाता है। कहीं ना कहीं यह सभी बिन्दु जम्मू-कश्मीर की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। परन्तु जिस प्रकार वर्तमान सन्दर्भ में इन परिस्थितियों एवं बिन्दुओं का लाभ लेते हुए जम्मू-कश्मीर पर एक अलग ही दृष्टिकोण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है वह पूर्ण ऐतिहासिक सत्य नहीं है।

प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जम्मू-कश्मीर पर नेहरू व पटेल की भूमिका और अन्य तत्कालिक कारणों पर विशेष प्रकाश डालते हुए *कश्मीर रियासत : नेहरू और पटेल* की भूमिका विषय पर फैली तमाम भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : भारत विभाजन का जम्मू-कश्मीर पर प्रभाव, जम्मू-कश्मीर राज्य की वर्तमान विषम परिस्थितियां व पं० नेहरू, पटेल दोनों महापुरुषों की जम्मू-कश्मीर पर वैचारिक स्थिति।

प्रस्तावना

जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में चर्चा होती है तो इस राज्य में व्याप्त विषम परिस्थितियों का ख्याल सर्वप्रथम सहज ही आ पड़ता है। हजारों वर्षों से अनेक आक्रमणों को झेलने वाला और विशिष्ट भौगोलिक संरचना से युक्त यह राज्य अपने अनुपम सौन्दर्य के लिए जाना जाता है परन्तु आजकल जम्मू-कश्मीर में व्याप्त नकारात्मक माहौल के बारे में ही बात की जाती है। प्रस्तुत शोध पत्र में यही बताने का प्रयास किया गया है कि जम्मू-कश्मीर में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियां भारत विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान जैसा पड़ोसी (जिसकी उत्पत्ति ही भारत विरोध के फलस्वरूप हुई है) तत्कालिक राजनैतिक परिस्थितियां, संयुक्त राष्ट्र संघ का पक्षपातपूर्ण निर्णय, पटेल व नेहरू की भूमिका इत्यादि सभी कारण सम्मिलित रूप से उत्तरदायी थे न कि इनमें से कोई एक विशेष कारण जैसा आज साबित करने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में बात की जाती है तो कुछ बातें जैसे राज्य की विलय प्रक्रिया, पटेल व नेहरू के कार्यों का विश्लेषण, राज्य को विशेष दर्जा इत्यादि बिन्दु सहज ही मन मस्तिष्क पर उभर कर आते हैं। इतिहास के तमाम छात्र ऐसे हैं जो इस प्रकार के विषयों पर पूर्ण जानकारी व समझ नहीं रखते हैं। ऐसे विषयों पर उनके समक्ष सही ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान न होना अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे विषयों पर तार्किक विश्लेषण किया जाए।

प्रस्तुत शोध पत्र *कश्मीर रियासत : नेहरू और पटेल की भूमिका* में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ यही दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जम्मू-कश्मीर पर जो सही तथ्य वास्तव में हैं वो सभी के समक्ष आने अति आवश्यक हैं। इतिहास की एक विशेषता है, इसका एक गलत तथ्य सम्पूर्ण अवधारणा को अर्थपूर्ण से अनर्थपूर्ण बना देता है। इसलिए इस शोध पत्र में उन

दिनेश सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर,
इतिहास विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
गंगेश्वरी, अमरोहा, भारत

सभी तथ्यों के अध्ययन करने का प्रयास किया गया जिससे कि शोध विषय के साथ सम्पूर्ण न्याय किया जा सके और भावी पीढ़ी इस गंभीर एवं महत्वपूर्ण विषय पर अपनी सम्पूर्ण एवं गहन समझ विकसित कर सके। यही मेरा सर्वप्रमुख उद्देश्य है इस विषय पर अध्ययन करने का।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का अध्ययन किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में वी० शंकर के माई रिमेन्सेसेज ऑफ सरदार पटेल वॉल्यूम-1 है व अन्य स्रोत द्वितीयक हैं। लैरी कालिन्स व डॉमिनिक लैपियर के ग्रन्थ आधी रात को आजादी में जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में और उस समय व्याप्त तत्कालिक परिस्थितियों का उल्लेख मिलता है। पी० डी० सम्गी की पुस्तक ए नेशनल होमेज में भारत के देशी रियासतों के एकीकरण के सम्बन्ध में बहुतायात में ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि होती है, विशेषरूप से जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में।

भारत विभाजन के पश्चात् भारत में उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों जैसे पाकिस्तान से आये हिन्दू निर्वासितों के जीवन का चित्रण, इसकी प्रमुख विशेषता है। एच० वी० हडसन की पुस्तक द ग्रेट डिवाइड में भी जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे काफ़ी जानकारी मिलती है, इस पुस्तक में पाकिस्तानी नीतियों के दुष्परिणाम के बारे में जिक्र मिलता है। साथ ही जिक्र मिलता है कि रजवाड़ों के विलीनीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्य बड़ा ही अनमोल था।

प्रस्तुत शोध पत्र में बलराज मधोक के ग्रन्थ जम्मू-कश्मीर एण्ड लद्दाख-प्रॉब्लम एण्ड सॉल्यूशन में उल्लेख मिलता है कि स्वराज और देश विभाजन, इन प्रक्रियाओं के साथ राज्यों के विलीनीकरण का प्रश्न जुड़ा हुआ था। कश्मीर के महाराज हरि सिंह की स्थिति विषम थी। राजा था हिन्दू किन्तु बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान थी। एक समय का वह हिन्दुस्तान का ही अविभाज्य भाग था, किन्तु धर्मांतरित प्रजा के कारण हिन्दुस्तान के विरुद्ध रहने वाला। यदि पाकिस्तान में विलीन हो जाए तो जम्मू-लद्दाख आदि भागों में रहने वाले हिन्दुओं का संहार निश्चित था, स्वयं राजा का भी निष्कासित होना अनिवार्य था। इसके विपरीत, हिन्दुस्तान में विलीन होने का निश्चय करे तो मुस्लिम जनता को राजा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए आमंत्रण देने जैसा था।

सुख सम्पत्ति राय भन्डारी की पुस्तक भारतवर्ष और उसका स्वतन्त्रता संग्राम तथा एस० गोपाल की पुस्तक जवाहर लाल नेहरू, अ बायोग्राफी में भी इस विषय पर विभिन्न महापुरुषों के विचारों का वर्णन मिलता है जिससे इस शोध विषय पर सही ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि होती है।

प्रस्तुत शोध विषय *कश्मीर रियासत : नेहरू और पटेल की भूमिका* में प्रयुक्त ग्रन्थों से आधुनिक दौर की गलत धारणाओं जैसे कश्मीर के बारे में असत्य बातों का प्रचार, नेहरू व पटेल के बारे में अनरगल तथ्य इत्यादि को असत्य सिद्ध करने में सहायता मिलती है।

मानवीय इतिहास में वैसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी। इसलिए मार्ग-निर्देशन कर सके, ऐसा कोई पूर्व उदाहरण हमारे सामने नहीं था। चालीस करोड़ लोगों का एक परिवार शताब्दियों से, एक ही धरती पर मिल-जुल कर रहता था। उसे अब टूट जाना था और किसी के सामने स्पष्ट नहीं था कि टूटने की प्रक्रिया ठीक-ठीक कैसी होती है, या उसे शुरू कहां से किया जाए।¹ इस देश विभाजन ने देश को पाकिस्तान जैसा पड़ोसी दिया जिसकी उत्पत्ति ही भारत विरोध के फलस्वरूप हुई और उसकी भारत विरोधी नीति से सर्वाधिक प्रभावित हमारे सिर का ताज कहा जाने वाला राज्य जम्मू-कश्मीर हुआ।

जम्मू-कश्मीर राज्य भारत की भौगोलिक संरचना पर एक विशिष्ट स्थान रखता है। प्रारम्भ से ही विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचारों को झेलने वाला यह राज्य अपने अन्दर एक वैभवशाली इतिहास को समेटे हुए है। सम्राट अशोक से लेकर कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का साक्षी बने इस राज्य ने मुस्लिम शासक जैन-उल-आबदीन के शासन को भी देखा। उसके बाद मुगलों व अंग्रेजों ने भी जम्मू-कश्मीर पर एक विशेष दृष्टिकोण रखा, परन्तु वर्तमान समय में जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति का आकलन करें तो ऐसा लगता है कि एक वैभवशाली इतिहास से परिपूर्ण यह राज्य आज प्रगति के जिस पथ होना चाहिए था वह आज नहीं है। आज यह राज्य जिस हाल में है उसके विभिन्न कारण हैं परन्तु उनमें राज्य की भौगोलिक परिस्थिति जिसके कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा राज्य में अशांति फैलाना व आजादी के बाद की राजनैतिक परिस्थितियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हो सकते हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर की आधुनिक परिस्थितियों के लिए जो एक विशेष कारण दृष्टिगोचर होता है, वो है आजादी के पश्चात् जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय की प्रक्रिया को सही तरीके से अंजाम न देना और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस कार्य का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से न सौंपना।

सम्पूर्ण भारत में फौली 500 से भी अधिक देशी रियासतों को एक सूत्र में बांधना बहुत ही कठिन कार्य था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस दुरुह कार्य को अपने हाथ में लिया व अपने विभाग के मंत्री के रूप में उनकी चिन्ता भारत को एक संयुक्त और सुदृढ़ देश के रूप में छोड़ जाने की थी और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन का हर पल अर्पित किया।² 1925 को हरि सिंह जम्मू-कश्मीर राज्य के महाराजा बने। एक हिन्दू राजा होने के पश्चात् भी जम्मू-कश्मीर की अधिकांशतः जनता मुस्लिम थी। इसी का लाभ लेते हुए 1932 में शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नामक संस्था गठित की। इसके आह्वान पर राज्य में कई बार कश्मीर छोड़ो आन्दोलन को चलाया गया और जिसके परिणामस्वरूप शेख अब्दुल्ला को कई बार जेल में डाला गया। इस कश्मीर छोड़ो आन्दोलन को पं० जवाहर लाल नेहरू का समर्थन प्राप्त था।

आजादी के पश्चात् जम्मू-कश्मीर के विलय के मुद्दे पर महात्मा गांधी ने महाराजा हरि सिंह से भेंट की

और यह इच्छा जाहिर की कि जम्मू-कश्मीर का विलय भारत के साथ होगा तो वह राज्य एवं उसकी जनता के हित में होगा परन्तु महाराजा हरि सिंह का मत उस समय स्पष्ट नहीं था। इन परिस्थितियों पर सरदार पटेल की विचारधारा अलग थी, वह कहते थे कि जम्मू-कश्मीर के विलय का प्रश्न वहां के शासक पर छोड़ दिया जाये और उनका यह भी कहना था कि अगर वहां के शासक को लगता है कि उनकी और उनके राज्य की दिलचस्पी पाकिस्तान के साथ है तो वह उनके रास्ते में आड़े नहीं आयेंगे।³

जम्मू-कश्मीर के द्वारा पाकिस्तान के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के पश्चात् भी पाकिस्तान का दृष्टिकोण जम्मू-कश्मीर के प्रति सकारात्मक नहीं था। पाकिस्तान लगातार जम्मू-कश्मीर पर दबाव बना रहा था जिससे कि महाराज दबाव में आकर विलय की घोषणा कर दे, दूसरी ओर पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। यह विद्रोह पंजाब एवं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रन्टियर प्रोविन्स की ओर से शुरू हुआ जिसमें रियासत की सेना में मुस्लिम सैनिकों ने विद्रोह किया तथा पाकिस्तान की तरफ से आ रहे आक्रमणकारियों के साथ हो गये।⁴ इस आक्रमण से जम्मू-कश्मीर की जनता की जान और माल को खतरा उत्पन्न हुआ और जगह-जगह पर लूटपाट और आगजनी की घटनाएं होने लगी। इन घटनाओं से चिन्तित होकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस व कश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार से मदद की अपील की।⁵

कश्मीर के फंसे हुए महाराजा ने अत्यन्त दीनता से भारत की सहायता मांगी थी। फील्ड मार्शल आकिनलेक से जो उग्र बहस हुई और पं० नेहरू ने तीव्र भावुकता प्रकट की, उसे ध्यान में रखकर लॉर्ड माउन्टबेटन ने समझ लिया था कि जम्मू-कश्मीर में सेना भेजे जाने की सम्भावना अधिकतम है। ऐसी कार्यवाही को न्याय-सम्मत अवश्य होना चाहिए, इस गरज से उन्होंने भारत सरकार को समझाया था कि जब तक महाराज अपने राज्य का विलय हमारे साथ नहीं करेगा। तब तक उसकी धरती हमारी नहीं बनेगी और वहां अपनी सेना उतारने के हकदार हम नहीं कहलाएंगे।

दूसरी ओर, लॉर्ड माउन्टबेटन यह मानकर चल रहे थे कि जिस जम्मू-कश्मीर की बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान है, उसे भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहिए। आपातकाल में महाराजा ने भारत से सहायता अवश्य मांगी है, लेकिन कश्मीर पर हक यदि किसी को है, तो पाकिस्तान को है।

इसलिए पं० नेहरू के विरोध की परवाह न करते हुए, गवर्नर-जनरल ने मंत्रिमण्डल से एक शर्त स्वीकार करवा ली कि जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय मात्र अस्थाई माना जाएगा। उसे स्थाई रूप तभी मिलेगा, जब वहां कानून और शांति की स्थापना हो जाए और कश्मीर की जनता मतदान करके अपनी इच्छा व्यक्त करे कि भारत के साथ जुड़ना चाहती है।⁶

पं० नेहरू का विचार था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय कर लिया जाये परन्तु यह विलय शेख अब्दुल्ला के सहयोग से होना चाहिए।⁷ उधर जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचन्द

महाजन चाहते थे कि भारतीय सेना शीघ्र अति शीघ्र जम्मू-कश्मीर आकर स्थिति को नियंत्रण में ले वरना महाजन पाकिस्तान जाने व जम्मू-कश्मीर जिन्ना को इस शर्त पर सौंपने के लिए तैयार थे कि श्रीनगर में घिरे एक लाख हिन्दुओं की रक्षा पाकिस्तान को करनी होगी।⁸ विपरीत परिस्थितियों में सरदार पटेल ने रक्षा मंत्री बलदेव सिंह से परामर्श करके इस स्थिति को नियंत्रित किया। इस समय भारतीय वायु सेना द्वारा की गयी यह कार्यवाही वास्तव में सराहनीय कार्य था और कुछ ही दिनों में आक्रमणकारियों को पीछे धकेल दिया गया।⁹ आगे चलकर जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय तो हो गया परन्तु इसके साथ ही एक शर्त भी लगा दी गई कि जम्मू-कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक जनमत संग्रह कराया जायेगा।¹⁰

जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी थी। पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को धोखे एवं हिंसा पर आधारित विलय की संज्ञा दी गई।¹¹ वर्ष 1947 के अन्त तक आते-आते सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा के विपरीत प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का निर्णय लिया। पं० नेहरू को यह सलाह लॉर्ड माउन्टबेटन ने दी थी क्योंकि लॉर्ड माउन्टबेटन का मानना था कि दोनों देशों के बीच इस मसले पर जंग छिड़ सकती है, ऐसी नौबत न आए इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सहारा लिया जा सकता है।

पं० नेहरू शुरू में इसके लिए तैयार नहीं थे परन्तु बाद में मान गए। लेकिन भारत जिस उम्मीद के साथ जम्मू-कश्मीर के मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ गया था उस पर सुरक्षा परिषद ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उसने आक्रमण से प्रभावित होने वाले भारत एवं आक्रमण करने वाले पाकिस्तान को एक जैसा ही माना। यह बात सुरक्षा परिषद द्वारा पेश कि किये गये प्रस्ताव से स्पष्ट हो जाती है।¹² सुरक्षा परिषद ने इस मामले में जैसा पक्षपातपूर्ण रुख स्वीकार किया था, वह प्रायः सब प्रकट है। मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है। भारत और आक्रमणकारियों को एक स्तर में रखकर शुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से उसने जैसा अन्याय किया, उस पर इस समय यहां लिखने की आवश्यकता नहीं।¹³ जिसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया जम्मू-कश्मीर का हिस्सा उसी के पास रह गया और वर्तमान में भी यही स्थिति है।

आमतौर पर पं० नेहरू की उनके आदर्शवाद व माउन्टबेटन के अत्यधिक प्रभाव में होने के कारण आलोचना की जाती है क्योंकि उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित होने के पश्चात् वहां पर जनमत संग्रह कराया जा सकता है। परन्तु यह भी सत्य है कि पं० नेहरू भी सुरक्षा परिषद में शक्तियों के राजनीतिक जोड़-तोड़ तथा पक्षपाती रुख को देखकर सुरक्षा परिषद से ऊब गये थे। उन्होंने अपनी बहन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को फरवरी 1949 में एक पत्र में लिखा था कि : "वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि सुरक्षा परिषद के काम में ऐसा पक्षपात होगा और फिर यह लोग समस्त संसार में सुव्यवस्था स्थापित करने का

दावा करते हैं। यह कोई अचम्बे की बात नहीं कि संसार टूट रहा है। इंग्लैण्ड तथा अमेरिका ने बहुत धिनौनी भूमिका निभाई। सम्भवतः इंग्लैण्ड ही परदे के पीछे से काम कर रहा था।¹⁴

सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी भी ऐसा अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ कि वे जम्मू-कश्मीर मामले पर कोई नीति बना पाते क्योंकि पटेल ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का मामला विशेष उत्तरदायित्व के साथ प्रधानमंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू जी के पास है या उनके पास विचाराधीन है।¹⁵ इस प्रकार की अपनी मजबूरी को वह जाहिर कर चुके थे और उनका स्पष्ट मत भी था कि भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर के प्रकरण को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना एक बड़ी भूल थी जिसका नुकसान हम आज तक भुगत रहे हैं।¹⁶ आज यह समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है कि जम्मू-कश्मीर में अमन चैन जैसी परिस्थिति लम्बे समय तक नहीं रह पाती है क्योंकि पाकिस्तान आज भी इस राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और इस कारण भारत और पाकिस्तान में हमेशा एक युद्ध की स्थिति बनी रहती है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर नीति पर वास्तविक रूप से स्वयं अपना क्या विचार रखते थे, यह भी एक विरोधावासा पैदा करता है क्योंकि कहीं वह कहते थे कि उनका नेहरू से कोई मतभेद नहीं है। कभी कहते थे कि कश्मीर पर जो भी हमारे बस में था वो सब कुछ किया। कभी वो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने के फैसेल पर असहमति जताते थे और तो और कभी उसका बचाव करते थे। इस सम्बन्ध में 03 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भाषण देते हुए पटेल ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने के फैसेल का समर्थन किया, उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर को लेकर हमारा यह मानना है कि दबी-छुपी जंग से बेहतर है खुलकर आमने-सामने लड़ना इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ गए। अगर जम्मू-कश्मीर को तलवार के जोर पर बचाया जा सकता है तो जनमत संग्रह का विकल्प ही कहां बचता है? हमें कश्मीर की जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय प्रकाश नारायण ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सत्य ही कहा था कि सरदार पटेल का दिमाग पढ़ना बहुत मुश्किल था, वह जम्मू-कश्मीर मामले पर क्या विचार रखते थे यह जान पाना बेहद ही मुश्किल कार्य था।

वर्तमान में जिस प्रकार से इन दोनों महापुरुषों की छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, वह दर्शाता है कि हमारे देश की राजनीति बेहद ही निम्नतम स्तर तक जा पहुंची है। अपनी राजनैतिक जमीन को विकसित करने हेतु राजनीतिज्ञ विभिन्न विचारधाराओं को जन्म देने का प्रयास करते नजर आते हैं जबकि सच्चाई इससे कहीं कोसों दूर है। आवश्यकता तो इस बात की है कि हमें पं० नेहरू व पटेल जैसी विभूतियों से सीख लेते हुए और उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भावी पीढ़ी को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए।

अंततः यहां पर यही कहना उचित होगा कि हमें पटेल-नेहरू विवाद जैसी परिस्थिति को उत्पन्न नहीं करना चाहिए और साथ ही इस प्रकार की व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ना चाहिए परन्तु वर्तमान समय में ऐतिहासिक

तथ्यों को तोड़ मरोड़कर नेहरू और पटेल के व्यक्तित्व व उनके विचारों को आमने-सामने रखकर यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों जम्मू-कश्मीर प्रकरण पर परस्पर विरोधी थे जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। पं० जवाहर लाल नेहरू का जम्मू-कश्मीर से विशेष लगाव था और वह भी हर प्रकार से चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर की समस्या का समाधान जितनी जल्दी संभव हो सके हो जाये परन्तु यह भी कहना गलत नहीं होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य भारतीय देशी रियासतों के विलय की समस्या के समान जम्मू-कश्मीर के प्रकरण में स्वतन्त्रता दी जाती तो शायद आज कुछ और ही परिणाम होता। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर को आज राज्य में व्याप्त कठिन एवं विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता।

अंत टिप्पणी

1. कालिन्स लैरी, लैपियर दॉमिनिक : आधी रात को आज़ादी, अनु प्रकाशन, जयपुर-2004, पृ० 150
2. सग्गी, पी० डी० : ए नेशनल होमैज, ओवरसीज पब्लिशिंग हाउस, बम्बई-1953, पृ० 11
3. शंकर, वी० : माई रिमेन्सेसेज ऑफ सरदार पटेल वॉल्यूम-1, द मैकमिलन कम्पनी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली-1974, पृ० 127
4. हडसन, एच० वी० : द ग्रेट डिवाइड, हचिन्सन एण्ड कम्पनी, लन्दन-1969, पृ० 446,447
5. द स्टेट्समैन, डेली न्यूजपेपर, दिनांक- 25 अक्टूबर, 1947
6. कालिन्स लैरी, लैपियर दॉमिनिक : आधी रात को आज़ादी, ऑप. सिट. जयपुर-2004, पृ० 271
7. दास, दुर्गा : सरदार पटेल कोरेसपॉन्डेन्स 1945-50 वॉल्यूम-1, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद-1974, पृ० 45
8. मधोक, बलराज : जम्मू-कश्मीर एण्ड लद्दाख-प्रॉब्लम एण्ड सॉल्यूशन, रिलायंस पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली-1987, पृ० 07
9. गुप्ता शिशिर : कश्मीर-ए स्टडी ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन्स, एशिया पब्लिशिंग हाउस, न्यूयार्क-1966, पृ० 188,189
10. शंकर, वी० : माई रिमेन्सेसेज ऑफ सरदार पटेल वॉल्यूम-1, ऑप. सिट. पृ० 132
11. दास, दुर्गा : सरदार पटेल कोरेसपॉन्डेन्स 1945-50 वॉल्यूम-1, ऑप. सिट. पृ० 77
12. गुप्ता शिशिर : कश्मीर-ए स्टडी ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन्स, ऑप. सिट. पृ० 148
13. भन्डारी सुख सम्पत्ति राय : भारतवर्ष और उसका स्वतन्त्रता संग्राम, अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर, पृ० 895
14. एस० गोपाल : जवाहर लाल नेहरू, अ बायोग्राफी, वॉल्यूम-2 लन्दन, पृ० 27,28 1979
15. आहलूवालिया, वी० के० : फेसेट्स ऑफ सरदार पटेल, कल्याणी पब्लिकेशन, लुधियाना-1974, पृ०163

16. कुलकर्णी, वी० बी० : दि इण्डियन ट्रि अम्बरेट-ए
पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ गांधी, पटेल, नेहरू,
भारतीय विद्या भवन, बम्बई-1969, पृ० 393